

'सवा साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ'

जयपुर देहात (दक्षिण) के नागरिकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल का बजट सौगातों के लिए आभार जताया

जयपुर, 5 मार्च। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर बजट सौगातों के आभार प्रदर्शन के लिए जयपुर देहात (दक्षिण) से आए प्रतिनिधिमंडल की आभार सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, कृषि, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनेक प्रावधान किए गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि जयपुर के विस्तार के साथ, आस-पास के इलाकों में सुख-सुविधाओं के विस्तार के लिये बजट में अनेक प्रावधान किये गये हैं।



जयपुर देहात (दक्षिण) की ओर से आए प्रतिनिधिमंडल ने बजटीय घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया। इस अवसर पर आमजन ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

बजट किसानों को आगे रखते हुए बनाया गया है। युवाओं के लिए भी सवा लाख पदों पर सरकारी भर्तियाँ और डेढ़ लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय हुए पेपरलीक प्रकरणों से राज्य का युवा परेशान था। हमने आते ही इन प्रकरणों में लिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। हमारे सवा साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं

हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे अपराध मुक्त राजस्थान की दिशा में उठाए गए कदमों से राज्य में गैंगवार और अपराध भी कम हुआ है।

शर्मा ने कहा कि हमने प्रदेश में पानी और बिजली को प्राथमिकता पर रखा। बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्य योजना पर काम कर रही है। हमारी सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही, राज्य को

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर का विस्तार होने के साथ ही, इसके आसपास के इलाकों का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुख-सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान 'एक ही लाल, भजनलाल भजनलाल' और 'दमदार मुख्यमंत्री, दमदार फैसले' जैसे नारों से पूरा पाण्डाल गुंजायमान हो उठा तथा

लोगों ने अभूतपूर्व बजटीय घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत किया। उपस्थित आमजन ने मुख्यमंत्री को 100 मीटर लम्बा साफा पहनाया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान जयपुर देहात (दक्षिण) के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, पूर्व मंत्री कन्हैया लाल, बूथ मण्डल एवं जिला पदाधिकारी सहित, बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे।

'राजीव गांधी शिक्षा की दृष्टि ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कांग्रेस ने जहाँ अख्यर की टिप्पणियों को खारिज किया है और राजीव गांधी को भारत के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक बताया है, वहीं भाजपा ने अख्यर की टिप्पणियों का पूरा लाभ उठाया है। पार्टी के आई.टी. सैल के अमित मालवीय ने व्यापक रूप से उक्त वीडियो को शेयर किया है। वीडियो देखकर यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह कहाँ

शुट किया गया था। अख्यर की टिप्पणियों ने भाजपा को विपक्ष के सवालियों के विरुद्ध बोलने के लिए खूब मसाला दे दिया है, जो (विपक्ष) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्रियों को लेकर सवाल उठाता रहता है। अख्यर के दशक के मध्य में राजीव गांधी के निकट सलाहकारों में एक माने जाने वाले, अख्यर पार्टी नेतृत्व द्वारा अपनी निरंतर उपेक्षा के कारण काफी

क्षुब्ध और नाराज़ हैं। पूर्व में उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसका शीर्षक था, "द राजीव गांधी आई न्यू-द फादर ऑफ इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन"। कांग्रेस ने यह कहते हुए अख्यर की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है कि "पार्टी में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और उनके पास पार्टी का कोई महत्वपूर्ण पद भी नहीं है। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने कहा, "उनके वक्तव्य पर

अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।" पार्टी के वरिष्ठ नेता, तारिक अनवर ने कहा कि अच्छे से अच्छे लोग भी स्कूल और कॉलेज एजाम में फेल हो जाते हैं। लेकिन राजीव गांधी राजनीति में फेल नहीं हुए। जब उन्हें जिम्मेवारी दी गई और वे प्रधानमंत्री बने, मेरा मानना है कि देश में बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ पाँच सालों में इतना कुछ हासिल कर लिया।

'अगर अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा, भारत हम पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाता है, यह सिस्टम अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, कभी भी नहीं था।

उन्होंने "अमेरिका फस्ट" की नीति पर जोर देते हुए कहा, "अन्य देश कई सालों से हम पर टैरिफ लगा रहे हैं, अब हमारी बारी है। हम भी उनके खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल करेंगे।"

प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स, जिनमें कैनडा, मैक्सिको, चीन, यूरोपियन यूनियन और भारत शामिल हैं, को नई टैरिफ नीति में निशाना बनाया जाएगा। यह टैरिफ अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में भारी बदलाव करने की नीति का प्रमुख अंग है।

ट्रम्प हमेशा से मानते हैं कि ग्लोबल ट्रेड रूल्स अमेरिका के लिए नुकसानदेह हैं और इसलिए वे रैसिप्रोकल टैरिफ पर जोर दे रहे हैं, अपने पहले कार्यकाल में, उनके प्रशासन ने ऐसे ही फैसले किए थे, पर, उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया था।

नया टैरिफ शुल्क देश के आधार पर लगाया जाएगा। इसमें सिर्फ शुल्क दर को ही नहीं बल्कि अन्य व्यवधानों पर भी ध्यान में रखा जाएगा।

'ट्रम्प की विदेश नीति में स्थायित्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) न लौट जाए और उसे अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई फिर न शुरू कर दे। अमेरिकन कांग्रेस के अपने भाषण में ट्रम्प ने एक खतरनाक आतंकवादी को संपने के लिए पाकिस्तान का आभार जताया। यह आतंकी काबुल हवाई अड्डे पर हुए बम विस्फोट में शामिल था। इस घमाके में अफगान नागरिकों सहित, 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जो अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान छोड़ने की घोषणा के बाद लौट रहे थे।

ट्रम्प ने अपने भाषण में यह भी बताया कि अमेरिका की खुफिया सेवा का एक सैनियर अफसर पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. के मुखिया से मिला और आतंकी को अमेरिका के सुपुर्द करने के मुद्दे पर काम किया, वह इस सप्ताह के अंत तक अमेरिका लौटने वाला है। इसी भाषण में उन्होंने अन्य देशों के साथ भारत को कोसा और अमेरिकन कारों पर ज्यादा टैरिफ के लिए भारत की आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत, अमेरिकन कारों पर शत-प्रतिशत टैरिफ लगाता है। ट्रम्प, आदतन फैक्ट चैक नहीं करते हैं और डेटा व तथ्यों के बारे जरा भी परवाह नहीं करते हैं।

असल में वर्तमान में भारत आयातित लज्जरी कारों पर 70 प्रतिशत टैक्स लेता

है, चाहे वह किसी भी देश से क्यों न हों, मोटर बाइक पर 40 प्रतिशत टैरिफ लगाता है। ट्रम्प ने पूर्व में हालीवूड सिनेमा मोटर बाइक और इन पर लगे टैरिफ का मुद्दा उठाया था। इसके बाद भारत ने मोटर बाइक से आयात शुल्क घटाया था। ट्रम्प डेटा और तथ्यों की परवाह नहीं करते हैं और अपनी ही सोच पर चलते हैं।

इसका नतीजा यह है कि अमेरिका अब जो करेगा, वो पूर्णतया अनिश्चित है। अमेरिका के विश्वस्तमित्र, जो कई दशकों से अमेरिका के साथ थे, अब अमेरिका का विकल्प तलाश रहे हैं। ताईवान दशकों से अमेरिकन सपोर्ट पर आश्रित था, पर अब अमेरिका का विकल्प ढूँढ रहा है। ताईवान, चीन से अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर था। डॉनल्ड ट्रम्प के एक्शन प्रतिशोधात्मक और विनाशकारी साबित हो रहे हैं। ट्रम्प ने ब्रिटेन को आदेश दिया है कि इंटेलिजेंस जानकारी किसी को न दी जाए, इस पर तुरंत अमल हो। अमेरिका ने यूक्रेन को भी गुप्तचर जानकारी देना रोक दिया है जो कि यूक्रेन की सैन्य कार्यवाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका सहयोगी देशों को भी गुप्तचर जानकारी नहीं दे रहा है। इस भ्रम और तनाव के बीच एक देश है, जो अमेरिका की बात नहीं मान रहा है और अमेरिका के पास इसका विकल्प नहीं है।

अमेरिका के बढ़े हुए शुल्क का सामना कर रहे चीन की संसद ने शी जिनिपिंग की अध्यक्षता में मौजूदा वर्ष के लिए अपनी आर्थिक योजना को अंतिम रूप दिया। ट्रम्प द्वारा लगाए गए शुल्क व तमाम धमकियों के बावजूद चीन ने 5 प्रतिशत ग्रोथ टारगेट निर्धारित किया है। इसके अलावा, अमेरिका के दण्डात्मक आर्थिक कदमों से निपटने के लिए चीन अन्य कदम उठा रहा है। चीन ने अमेरिकन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे उनके कामकाज तथा प्रॉफिट को नुकसान पहुँचा है। चीन ने अब अमेरिका को महत्वपूर्ण खनिजों व कच्चे माल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था व कम्पनियों को नुकसान हो सकता है। कुछ बेहद महत्वपूर्ण खनिजों का कुल 85 प्रतिशत चीन के अधिपत्य में है। ये पदार्थ रक्षा उद्योग व ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका, यूक्रेन से यह पदार्थ हासिल करना चाहता है, पर जैलैन्स्की से विवाद के बाद यह योजना विफल हो गई है। ट्रम्प ने वादा किया है कि वे यह पदार्थ ग्रीनलैंड से हासिल करेंगे, चाहे जो हो जाए। संकीर्ण दृष्टिकोण वाले ट्रम्प अमेरिका के तटों से आगे नहीं देख पा रहे हैं। वे अपने ही बनाए गड़ड़ों में गिर सकते हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यू.पी., ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थितियों को फ्रीज कर ही रखा है। स्टालिन ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया जना भी प्रस्तावित किया, जिसमें सभी दक्षिणी राज्यों के सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हों। यह समिति इस मामले में जनता में जागरूकता पैदा करे तथा सीटों की सम्भावित कमी को रोकने के लिये आवश्यक हो चुके संघर्ष को आगे बढ़ाये। इस संघर्ष के क्षेत्र और पहुँच को विस्तार देते हुये तथा इस प्रक्रिया में अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों को शामिल करते हुये, स्टालिन ने इस मुद्दे को सबसे ऊपर पहुँचा दिया। यह मुद्दा राज्य विधानसभा के चुनावों तक की अवधि में छाया रहेगा तथा इसके साथ तीन भाषा फॉर्मूले का विवादस्पद मुद्दा भी जुड़ा रहेगा। इस प्रकार, उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा को बिल्कुल अलग-थलग कर देने की व्यवस्था कर दी है। विशेष रूप से, अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिये अनामद्रमुक तथा भाजपा के गठबंधन की बैक-चैनल चर्चाओं की पृष्ठभूमि में, परिसीमन तथा भाषा के भावनात्मक मुद्दे को लेकर हुई अज्ञात की मीटिंग ने उक्त दोनों

पूर्व मित्र-दलों के बीच प्रभावी रूप से अलगाव पैदा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। प्रसंगवश बता दें कि केवल भाजपा ने ही आज की इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया था, जिसमें कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुये तथा ये प्रस्ताव तमिल और तमिलनाडु के हित में माने गये। परिसीमन सम्बंधित प्रस्ताव में, इस कार्यवाही को नाजायज बताया गया। स्टालिन द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव को सर्वदलीय मीटिंग में सर्वसम्मति से पारित कर दिया। प्रस्ताव में स्टालिन ने कहा, "चूँकि दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया, इसलिए इन राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या कम करना अनुचित है। केन्द्र को (सीटों के मामले में) 2026 के बाद के 30 वर्षों तक वर्तमान व्यवस्था यथावत रखनी चाहिये, क्योंकि वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री (अटल बिहारी वाजपेयी) ने वादा किया था कि परिसीमन का निर्णय 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा। अन्य राज्यों से भी जनसंख्या - नियंत्रण के उपायों को क्रियान्वित कराया

जाना आवश्यक है।" प्रस्ताव में भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की परिसीमन की कवायब की निन्दा भी की गई। सर्वदलीय मीटिंग के प्रस्ताव में तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिणी राज्यों के राजनैतिक प्रतिनिधित्व के लिये गंभीर खतरा बताया। स्टालिन ने कहा कि "केन्द्र की भाजपा सरकार इस मुद्दे पर लोकसभा में राज्य के 39 सांसदों की आवाज़ को सुनने तक के लिये तैयार नहीं है। हमें 2026 की जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन का साफ तौर पर विरोध करना पड़ेगा।" उन्होंने कहा, "हमें इस मुद्दे पर दृढ़ रुख अपनाना होगा।"

फिल्म स्टार विजय की अभी -अभी लॉन्च हुई राजनैतिक पार्टी "तमिलतागा वैट्टी कडुगम" तक भी इस सर्वदलीय मीटिंग में शामिल थी। इसके अलावा, भाजपा के मित्र दल, जैसे "पट्टाली मक्कल काची" तथा अन्य भी मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन भाजपा के दो अन्य मित्र दलों - "तमिल मनीला कांग्रेस" तथा अभिनेता सीमान के नेतृत्व वाली "नाम तमिल काची" ने मीटिंग का बहिष्कार किया। स्टालिन ने कहा, "परिसीमन

दक्षिण भारत के ऊपर लटकती तलवार जैसा है। यह परिसीमन 2026 की जनगणना के आधार पर होगा। अगर केन्द्र ने मौजूदा 543 लोकसभा क्षेत्र कायम रखे, तो तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व में 8 सीटें कम कर दी जायेंगी।" स्टालिन ने समझाया कि अगर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 848 कर दी गई तथा परिसीमन प्रतिशत आधार पर किया गया तो तमिलनाडु को 22 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। स्टालिन ने कहा, "लेकिन, अगर परिसीमन वर्तमान जनसंख्या के आधार पर किया गया तो तमिलनाडु को सिर्फ 10 सीटें मिलेंगी। दोनों ही तरीकों से अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन तमिलनाडु की आवाज दबा दी जायेगी। हमें इस घबड़घबड़ को पराजित करना है।" मीटिंग में पारित एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर सांसदों की संख्या बढ़ाई जानी है तो संविधान में ऐसा संशोधन किया जाये कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा तथा राज्यसभा में तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिणी राज्यों की सीटें आनुपातिक रूप से बढ़ाई जायेंगी।

MARUTI SUZUKI ARENA

पुरानी छोड़े, नई लाएं!

अपनी पुरानी कार स्क्रेप करें और भविष्य की ओर चलें।

ADDITIONAL SCRAPPAGE AND EXCHANGE BENEFITS UP TO ₹25 000*

01 March 2025

Fuel will not be provided to vehicles older than 15 years at petrol pumps in Delhi after March 31.

The Delhi government will stop fueling vehicles over 15 years old at city stations after March 31, according to Environment Minister Manjinder Singh Sirsa. The decision follows a meeting on air pollution, with Sirsa stressing the government's efforts to tackle vehicular emissions.



BEST SCRAPPAGE VALUE#



BEST EXCHANGE OFFERS



UPTO 100% ON-ROAD FINANCE

3 years 100 000 km WARRANTY**

विशेष ऑफर

SWIFT ₹58 100* | WAGONR ₹73 100*



SCAN TO CONNECT TO SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

T&C apply. Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. Offers vary across variants. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on select models/variants. Above mentioned savings amount is the value of maximum savings on select models. Offer valid with select financiers only. **3 years or 100 000 km - whichever is earlier. #Scrapage Offer valid for limited time only. For more details, please contact your nearest ARENA dealership. *Scrapage value offer is brought to you by Maruti Suzuki Toyota India Private Limited (a joint venture company between Maruti Suzuki India Ltd and Toyota Tsusho Group). Above offers are valid till 31st March 2025.

VISIT YOUR NEAREST MARUTI SUZUKI ARENA DEALERSHIP TODAY OR E-BOOK AT WWW.MARUTISUZUKI.COM | CALL 1800 102 1800

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाइंट मॉडिया, आजाद मार्ग, मेन रोड, आर्य, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.ए.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय: पलायथा हाजस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033 बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाजस, हनुमान हथा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय: - जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल परिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय: - जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908